इस प्रसंग में उन्होंने कहा है कि केन्द्र के खिलाफ यदि हमको आर्म्ज रेजिस्टेंस भी स्टार्ट करना पड़े तो हमको करना चाहिये। किस की उपस्थिति में कहा ? यदि यह बात सिर्फ मीर वाएज फारुक ने कही होती तो हमको तकलीफ नहीं होती, लेकिन जिस व्यक्ति की मौजूदगी में यह बात कही गई वह जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री थे। मुख्य मंत्री जी ने भी उस मीटिंग में कहा था—

> "The Chief Minister, who spoke briefly after Mirwaiz, endorsed his views by saying that Mirwaiz had already told the people everything and he would not like "to add anything" to what he had already said."

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue after 6 O' Clock we are now taking up the Private Members' Business from 3 to 5.30 P.M. Then, there is the Half-An Hour Discussion. I understand that it has already been announced that this can be takan up at 6 O' Clock. So, you must remain here to continue your speech.

15.00 Hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we go to the next item, Private Members Business. Minister please.

SHRI BUTA SINGH : You are trying to remark that the remaining portion of the Calling Attentions will be taken up after the discussion. Unfortunately, today it is not possible to sit beyond 6 O' Clock. Can it be taken up on the next working day ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, if the House agrees, well and good. Yes. It will be continued next Monday. Is it the pleasure of the House to concede the demand of the Minister for Parliamentary Affairs ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : (Bombay North East) : He should consider our demands also on occasions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jalil Abbasi.

15.01 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBTRS, BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty-fifth Report

SHRI KAZI JALIL ABBASI (Domariaganj) : I beg to move :

> "That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd November, 1983.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The que-s tion is :

> "That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd November, 1983."

The motion was adopted.

15.03 Hrs.

RESOLUTION *RE* INDUSTRIAL SICKNESS—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri E. Balanandan. He is not present. Since Shri Balanandan, the mover of the resolution is not present, his speech would be considered that it has been concluded.

Now I call upon other speakers.

Shri Girdhari Lal Vyas.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी कभी तो टाइम ज्यादा दे देते हैं लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : How much time you want ?

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : Only half-an-hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Granted. All right.

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह जो औद्योगिक रुग्णता यानी इन्डस्ट्रियल सिकनैस के बारे में प्रस्ताव रखा गया है, यह बहुत अच्छा है। पूंजीपतियों के द्वारा जो इन्डस्ट्रियल सिकनैस फैलाई जा रही है, उस की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमारे देश के मजदूरों का और उत्पादन का हो रहा है, इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। ये जितने पूंजीपति लोग हैं, ये जानबूझ कर इंडस्ट्री को सिक करते हैं। वे 85 90 परसैन्ट तक लोन आप की फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से ले लेते हैं और फिर इंडस्ट्री को सिक कर देते हैं। आप के अधिकारी भी इन से मिले हुए हैं और जितने भी यूनिट्स सिक होते हैं, उसके बाद जितने पैसे की आवश्यकता होती है, उतना पैसा उनको मिलता है और उस के बाद भी वह इंडस्ट्री या यूनिट सिक रहती हैं और उसकी सिकनैस नहीं जाती है। इस तरीके से करोड़ों रुपया वे फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से ले लेते हैं और उसके बाद भी स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि दिन ब दिन यह सिकनैस बढ़ती ही जा रही है।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I gave an amendment. I want first to move that amendment and then he must be allowed to speak. I am on a point of order.

MR. DEPUTY SPEAKER : You are right. I am uphold your point of order.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, I beg to move :

That in the resolution.

after "employees" *insert*

" the root causc being the creation of rival unions of workers as also the emergence of musclemen as leaders"

MR. DEPUTY SPEAKER : Now both the Resolution and the Amendment are before the House.

Mr. Vyas will continue his speech.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस तरीके से पूंजीपति अपनी इंडस्ट्रीज को सिक करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने खजाने में भर रहे हैं और देश में ब्लैक मनी क्रियेट कर रहे हैं।

हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज को देखते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज को हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब देखते हैं। आप देश में कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए चाहे कपड़े की ही, चाहे सीमेंट की हो, चाहे पेपर की हो, सब इंडस्ट्रीज के मालिक फ्राडुलेट तरीके से करोड़ों रुपये का नुकसान भारत सरकार को पहुंचा रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिये।

मैं निवेदन करता हूं कि इन पूंजीपतियों की आपकी फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस भी मदद करती हैं। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस हैं वे सब इन पूंजीपतियों की दलाल हैं और जानबूझ कर इनको पैसा देते हैं। मेरे क्षेत्र में एक मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है। वह एक बहुत अच्छा यूनिट है। लेकिन उसका जो मालिक ** वह बराबर फ्राडुलेंट कार्य करता है। जब वह रुई खरीदता है तो उसमें भी गड़-बड़ करता है।

SHRI MOOL CHAND DAGA : He cannot make any allegation against a person unless he has given notice in writing to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record.

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या आप उस पूंजीपति की मदद करना चाहते हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, some enmity has developed between the two Rajasthan Members of Parliament.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस पूंजीपति का जो पिता था उसने भी इस मिल को सिक बनाया। उसके बाद करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने उस पर खर्च किया। एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा रुपया

*Not recorded.

उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इस मालिक ने अपने कब्जे में आने के बाद इस मिल में फिर फाड्डलेट कार्य शुरू कर दिये। रुई खरीदने में घपला, कपड़ा बेचने में घपला। लाखों रुपये के भयंकर घपले इसमें किये गये। इस मिल का एक हौजरी डिपार्टमेंट चलता है। उसमें दुनिया में मशहूर मीटेक्स बनियान बनती है। उसमें भी घपला किया हुआ है। उसकी रुई खरीदने में भी घपला किया जाता है और बनियान बेचने में भी घपला किया जाता है। इस तरीके से आपकी यूनिटें सिक बनायी जाती है और कड़ी मेहनत से कमाये हुए इस देश के करोड़ों रुपयों का ऐसे उद्योगपति दुरुपयोग कर रहे हैं। आप की मशीनरी उनसे मिली हुई है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है।

आपको याद होगा कि मैंने एक साल पहले इस पर प्रश्न उठाया था और कहा था कि किस प्रकार से इसने अपने असेट्स को वहां से ट्रांस्फर किया और उन असेट्स से कोटा के अन्दर एक सिनेमा हाल खड़ा किया। इस मिल के असेट्स इस मिल के मालिक द्वारा ट्रांस्फर किये जा रहे हैं और इस मिल को सिक बनाया जा रहा है। आपने उस समय यह जवाब दिया था कि इस को जो फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस पैसा देती हैं, उनकी इस सबको देखने की जिम्मेदारी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर इसके बारे में इतना कहने के बाद भी इस मिल को तीन करोड़ रुपया मिला। इस प्रकार से आपकी फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस जो डूबती हुई नावें हैं उनमें और भी पैसा लगाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार की हालत देश में आपकी फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस ने कर रखी है। जो देश में सिक यूनिट्स हैं वे पैसा लेकर अपने यूनिट्स को और भी सिक बनाते हैं और ब्लेक मनी पैदा करते हैं, यह स्थिति है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान स्पिनिंग एवं बीविंग मिल है। उसका मालिक सेठ झुंझुनवाला है। उस यूनिट से 3-4 इंडस्ट्री खड़ी कर ली हैं। दिल्ली में भी एक इंडस्ट्री है। एक खादीग्राम के नाम से भी इंडस्ट्री चल रही है। मोनापली हाउसेस में उसका नाम भी आने लगा है। आज वह सौ करोड़ के आस-पास मालिक हैं। यह उसने इसी मिल के जरिए से कमाया है। इस मिल के सारे असेट्स दूसरी जगह ट्रांस्फर कर दिए हैं और इस मिल को उसने सिक बना दिया है। 6 महीने पहले यह सिक हो गई और बंद हो गई। राज्य सरकार ने इसको वापिस खुलवाया। आज वह बिल्कुल बीमार की तरह चल रहा है। आज वहां 3000 मजदूर काम करते हैं लेकिन मुश्किल से सौ-दो सौ को ही काम मिल पाता है बाकी को ले आफ कर रखा है। बाकी किसी को काम नहीं दिया जाता। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस का उस पर साढ़े 6 करोड़ रुपया बकाया है। अब उसने राजस्थान स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल का नाम बदल कर भीलवाड़ा स्पिनर्स रख दिया है। बाकी जो शेयरहोल्डर्स थे उन सबको धोखा देकर, सरकार को धोखा देकर अपने परिवार वालों के नाम पर नई इंस्टीट्यूशन कायम कर दी है। मैंने इस बारे में फाइनांस मिनिस्टर को पत्र लिखा था कि इस प्रकार से धोखा देने की कोशिश की जा रही है। फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और समय रहते संभलिए। अपना पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। मगर फाइनांस मिनिस्टर साहब का वही जवाब मिला कि यह हमारा काम नहीं है। हम इसको नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार के ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। सारा पैसा डूब जाये, बरबाद हो जाए लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं करते। हमने कहा कि जितना पैसा दिया है सारा वसूल होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार की स्थिति आज हो रही है। सरकार समय रहते इन पूंजिपतियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

कितनी इकाइयां रुग्ण हो गई हैं। भीलवाड़ा में 10-12 करोड़ रुपया छोटी-छोटी इकाइयों को लोन के रूप में दिया है। बैकवर्ड जिला

होने की वजह से बहुत सा पैसा सबसिडी के रूप में मिलता है। सबसिडी खाने के लिए लोग इस प्रकार की संस्थाएं बनाते हैं और सरकार से कर्ज लेकर सबसिडी खा जाते हैं और उसके बाद संस्थाओं को रुग्ण कर देते हैं। उनको ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद वहां के मजदूरों की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

सरकार चाहती है, श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं कि देश में लोगों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो। इसलिए आपकी मिनिस्ट्री का फर्ज है कि इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज का पूरा ध्यान रखिए। लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी जा रही। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वे केवल इस प्रकार की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि इन पूंजीपतियों की दलाली करो और कुछ न कुछ मिलता रहे। इस प्रकार की स्थिति है। अगर देश को ऊंचा उठाना है, रोजगार देना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो इन पूंजीपतियों का ख्याल करिए। भारत सरकार जब कर्मशियल बेसिस पर इंडस्ट्री लगाती है तो बनिएं की तरह उस पैसे का ध्यान रखना चाहिए। ये सफेद हाथी जो आई ए एस आफिसर हैं, ये उस पैसे का खयाल नहीं करते। बाद में आपको और हमको परेशानी होगी जिन्होंने जनता को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाना है। जिसकी जिम्मेदारी देश को आर्थिक तौर पर मजबूत और ऊंचा उठाने की है और इस बात की भी है कि हर हाथ को काम मिले। ऐसी योजना हम जब तक नहीं बनायेंगे तब तक हम किस तरीके से अपनी व्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली बनायेंगे तथा यहां का उत्पादन और एक्सपोर्ट बढ़ायेंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। बंगाल में क्या हो रहा है? तमाम इंजीनियरिंग और पटसन यूनिट्स बंद पड़े हुए हैं। दूसरी जगहों पर कई कपड़े के मिल बन्द पड़े हुए हैं। आपने बम्बई में 12-13 मिलों का अधिग्रहण किया उसी प्रकार से जितने सिक यूनिट्स हैं उनको क्यों नहीं नेशनलाइज करते। आज एक नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का प्रश्न था। उसमें बताया गया कि 1982-83 में 76 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह क्यों नहीं होगा क्योंकि ऐसे लोगों को आपने टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में बैठा रखा है जिनको बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं और जो इस बात को नहीं समझते कि इसमें फायदा होना चाहिए या नुकसान। उनको तो सभी तरह के आराम मिलने चाहिए। हमारे यहां व्यावर में टैक्सटाइल मिल नेशनलाइज की। वहां पहले ठीक काम चलता था। लेकिन बाद में ऐसे अधिकारी को वहां पर बैठा दिया जिसने दोनों मिलों का बट्ठा बैठा दिया। आपने एडवर्ड मिल और लक्ष्मी मिल में आई० ए० एस० अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बैठा दिया। उनके द्वारा किस प्रकार से सारे मजदूरों को नुकसान हुआ, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, अच्छी मिल है। उसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। वहां के सेठ की बेईमानी की वजह से जिस प्रकार से वहां शोषण हो रहा है, उसके कारण वह मिल घाटे में है। उसके असेट्स ट्रांसफर कर दिए, ऐसी व्यवस्था वहां पर है। जितने भी यूनिट्स नेशनलाइज किए, वे कभी घाटे में जाने वाले नहीं हैं। पूंजीपतियों ने उनको सिक जान-बूझकर बनाया है। जिन अधिकारियों को वहां पर बैठाया है उनके दिमाग आसमान पर चलने वाले हैं। वे जमीन पर चलने वाले लोग नहीं हैं। वे, यूरोप में और दूसरी कन्ट्रीज में घूमते-फिरते हैं। उसके बाद मिल की क्या हालत होती है, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसलिये, ऐसे लोगों को यहां पर बैठा देंगे तो सिक इन्डस्ट्रीज को कभी भी ऊंचा नहीं उठा सकेंगे।

आप बिजली विभाग देख लीजिए। हमारे यहां जितने भी वैस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, यू० पी० और दिल्ली में इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड्स हैं, वे सफेद हाथियों की वजह से घाटे में चल रहे हैं। सफेद हाथी बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिलकर इसको खा रहे हैं। इसका उत्पादन भी

सिर्फ 45 प्रतिशत दिखाया गया है। उसके बाद सारी बिजली चोरी हो जाती है। जितने भी रोडवेज हैं वे भी सिक हो रही हैं क्योंकि यहां पर भी बड़े-बड़े लोगों को बैठा देते हैं। ऐसे लोगों को रोड ट्रांसपोर्ट का कोई अनुभव नहीं है जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हमारी जितनी योजनाएं हैं, हमारी नेता श्रीमती गांधी के जो कार्यक्रम हैं, वे किस तरीके से कामयाब होंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Vyas, there is a mike system. You may therefore speak at a very low ebb. It is your habit. Anyway I am trying to help you. You become tired after 15 minutes. You may take a few more minutes and then conclude.

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरी आवाज थोड़ी तेज है। मैं कह रहा था इस तरह से जो सरकारी यूनिट्स हैं वह भी रुग्ण होती जा रही हैं। प्राइवेट की तो हालत खराब है ही, सरकारी कल कारखाने भी नुकसान दे रहे हैं। कल परसों हमारी प्रधान मंत्री ने पब्लिक सैक्टर के ऐग्जीक्यूटिव्ज से कहा है कि अगर यूनिट्स में नुकसान होता है तो वह सारे देश, मजदूरों और गरीब लोगों का नुकसान है जिनका पैसा इनमें लगा है। नुकसान सफेद हाथियों के कारण होता है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं।

खेतड़ी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है ? गरीब लोगों की जमीनें ऐक्वायर की कापर कामप्लैक्स के लिये। लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट तक उनको परेशान किया जा रहा है। 20 साल हो गये अभी तक गरीबों को कम्पेन्सेशन नहीं मिला। सरकारी अधिकारी अपने टी० ए० और डी० ए० का ही ध्यान रखते हैं जो उनको सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर आने के लिये मिलता है। प्रोजेक्ट राजस्थान में लेकिन उसका दफ्तर कलकत्ता में लगा रखा है और पेशियां जोधपुर और दिल्ली में कराते हैं ताकि अधिक से अधिक टी० ए०, डी० ए० ले सकें। जो रुपया गरीबों को कम्पेन्से-शन में देना चाहिये उससे ज्यादा रुपया अधिकारियों के टी० ए०, डी० ए० पर खर्च हो गया। गरीब बेचारे परेशान हैं। कहा यह गया था कि जिनकी जमीनें ली गई हैं उन लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हो यह रहा है कि अधिकारी जिस प्रान्त का होता है, वहीं के लोगों को रखता है, चपरासी तक भी अपने ही प्रान्त का रखते हैं। बिहार का हुआ तो बिहारी को, बंगाल का हुआ तो बंगाली को, महाराष्ट्र का अधिकारी हुआ तो महाराष्ट्र के लोगों को ही चपरासी बनाकर ले आयेगा। क्या राजस्थान में क्लास चार के कर्मचारी भी नहीं मिल सकते हैं ? हमारे आदमियों को चाहे टैक्नीकली ट्रेन्ड हों, नहीं रखा जाता है, बल्कि बाहर के लोगों को ही रखा जाता है इस तरह का अत्याचार हमारे साथ अधिकारियों द्वारा हो रहा है। एक तो वैसे ही हमारे यहां इंडस्ट्रीज 1 परसेंट हैं लेकिन उनमें भी इस प्रकार का रवैया विभाग के लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। इस तरह की बीमारियों को आपको रोकना चाहिए। अगर मजदूर बीमार होता है तो देश बीमार हो जाएगा क्योंकि वह देश की रीढ़ की हड्डी है। जितनी ज्यादा उसको मजदूरी और सहूलियत मिलेगी उतनी ही व्यवस्थायें मजबूत बनेंगी। आपके विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिये कि कोई भी इकाई बीमार न हो। और अगर बीमारी होती है तो फौरन कार्यवाही करनी चाहिये। इस बात को देखने के लिये एक जिम्मेदार संस्था होनी चाहिये जो देश के लगे हुए धन की रक्षा करे।

20,000 करोड़ रुपया प्राइवेट सैक्टर में लगा हुआ है, और इससे ज्यादा पब्लिक सैक्टर में लगा हुआ है। इसलिये आपकी जिम्मेदारी है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से देखें ताकि यह यूनिट्स सिक न हों और साथ ही देश के मजदूर का नुकसान न हो।

इसलिए इन पूंजीपतियों के द्वारा जो फर्जी रुग्णताएं लगाई जा रही हैं, इनको रोका जाना

चाहिए और उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में वह ऐसा न कर सकें और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसमें वह फिर इस प्रकार का काम न कर सकें जब तक किसी कानून के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था उनकी सजा की नहीं बनायेंगे तब तक वह ऐसा करने से चूकेंगे नहीं और साथ ही बडे बड़ अधिकारी जो पब्लिक सैक्टर में बैठे हुए हैं वह भी इनका शोषण करने से नहीं चूकेंगे ।

अगर कोई इंडस्ट्री, चाहे पब्लिक सैक्टर में हो या प्राइवेट सैक्टर में हो, बीमार होती है तो उसके बारे में इन लोगों का जवाब तलब किया जाना चाहिए औद जितना नुकसान होता है वह इन पूंजीपतियों और अधिकारियों की जमीन-जायदाद से वसूल किया जाना चाहिए, तभी हमारा इन्डस्ट्रियल कम्पलेक्स सही हो सकेगा ।

इंडस्ट्रीज में हमारे मजदूर बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, वही इस देश को बनाने वाले हैं । अगर मजदूर कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है इसलिए मजदूर को मजदूरी, नौकरी देने की नितान्त आवश्यकता है । जब वह लोग सही काम पर लगेंगे तभी हमारा देश फल-फूल सकेगा ।

श्री बालानन्दन जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि रुग्ण इकाइयों को सरकार देखे, ये यूनिट्स बीमार न हों इसके लिए समय रहते इन पर अंकुश लगाया जाये ताकि यह बीमार न पड़ें चाहे सरकार इन्हें अपने हाथ में ले या प्राइवेट सैक्टर में ये रहें लेकिन इस बात का इलाज तुरन्त होना चाहिए ताकि देश को किसी प्रकार का नुकसान न हो । इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : You are supporting the resolution. It is for the first time Mr. Vyas is supporting a resolution moved by CPM. Now Mr. Jagpal Singh.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : I have to go somewhere at about 4 P.M.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yon ask if Mr. Jagpal Singh can oblige you. He is going to take 10 minutes only.

SHRI JAGPAL SINGH (Hardwar) : I don't mind. I will oblige him.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please wait; after 10 or 15 minutes I will call you. Mr. Jagpal Singh—you may please take 10 or 15 minutes and conclude.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मोशन श्री बालानन्दन जी लाए हैं, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । जिस ढंग से इस सरकार ने पूंजीवाद को बढ़ाने का काम किया है, दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में शायद ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा । एक तरफ इस देश के 52 प्रतिशत लोग बिलो-पावर्टी लाइन रह रहे हैं जिनको कपड़ा, खाना, मकान, शिक्षा और दवा भी नहीं मिलती और यही नहीं 36, 37 सालों की आजादी के बाद भी आज इस देश में करोड़ों-करोड़ों लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता है । ऐसी सरकार को मैं समझता हूं कि सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

इंडस्ट्रियल सिकनैस पर जो संकल्प आया है इसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ हिन्दुस्तान के मजदूरों को पूंजीपतियों के कारण भयंकर दिन देखने पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकारी साधनों का नाजायज फायदा उठाकर हैवी इंडस्ट्रीज खड़ी की जा रही हैं और उसके मालिक इस देश में फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्ज से करोड़ों-करोड़ों रुपया लेकर कैसे उसका मिस-यूज करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हिन्दुस्तान में 50 प्रतिशत से ज्यादा इंडस्ट्रीज अभी तक सिक हैं । आज आपको मजबूरी में करोड़ों-अरबों रुपए का घाटा उठाकर टेक-ओवर करना पड़ता है लेकिन सरकार के

पास इस तरीके के पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का साधन नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार में बैठे हुए लोग और इनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग यहां के कैपिटलिस्ट्स और कैपिटलिज्म के साथ साजिश किए हुए हैं। इसलिए करोड़ों रुपए का फायदा उठा कर और करोड़ों अरबों रुपये तनख्वाह और प्राविडेंड फंड में देकर वह अपनी इंडस्ट्री को सिक घोषित कर देते हैं और सरकार उनके साथ मिल कर उन इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करती है। लेकिन इससे समस्या क्या पैदा हो रही है? मैं बुनियादी तौर पर कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकार की इस एकोनामिक पालिसी का विरोध करता हूं, सरकार को हैवी इंडस्ट्री लगाने की योजना भविष्य में नहीं बनानी चाहिए। जहां देश के अन्दर हजारों और करोड़ों की तादाद में मैन्युअल पावर हो, इतने आदमी हों, ऐसे मुल्क के अन्दर हैवी इंडस्ट्री को लगाना इस देश की अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ना है। इस देश के अन्दर होना यह चाहिए था कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हजारों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता। लेकिन हैवी इंडस्ट्री लगा कर उन सभी हाथ से काम करने वाले लोगों का पेशा ही खत्म कर दिया गया है। मैं सुझाव के तौर पर कहूंगा कि भविष्य में हैवी इंडस्ट्री का लाइसेंस कम से कम उन कैपिटलिस्ट्स को न दिया जाय जिन के रहते हुए इंडस्ट्री सिक हो जाती है और इस देश के लोगों पर करोड़ो करोड़ो रुपये का भार पड़ता है। ऐसे लोगों को भविष्य में हैवी इंडस्ट्री का लाइसेंस कदापि नहीं देना चाहिए।···(**व्यवधान**)···आप भी सही कह रहे हैं कि वह दूसरे नामों से लेते हैं लेकिन सरकार की नालेज में एक एक चीज है। सरकार के पास उन सभी कैपिटलिस्ट्स की लिस्ट भी है और कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कौन इंडस्ट्री चल रही है यह सब उसकी नालेज में है।

अभी जो 13 टैक्सटाइल मिलों का अधिग्रहण सरकार ने किया है उनमें जो अभी आया कि 14 करोड़ का घाटा है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन सोर्सेज के द्वारा आप ने बम्बई की उन 13 टैम्सटाइल मिलों का यह घाटा तय किया? क्योंकि हमारे हिसाब से कम से कम एक अरब रुपए का घाटा सरकार को और इस देश के लोगों को उठाना पड़ा है। आप ने उन इंडस्ट्रयलिस्ट्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। हिन्दुस्तान का कोई छोटा व्यापारी, दूकानदार या और कोई व्यक्ति सरकार से या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन से पैसा लेकर काम नहीं कर पाता है और उसकी वापसी नहीं हो पाती है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं। लेकिन आज तक किसी पूंजीपति को जेल नहीं भेजा गया। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी के शासन में एक बार ऐसा हुआ था लेकिन आज तक इन्दिरा जी के शासन में एक भी पूंजीपति को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया। बिना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के वह लाक आउट करके चले जाते हैं और आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि सरकार की इजाजत के बगैर और सही कारणों के यगैर जो भी कैपिटलिस्ट लाक आउट करे उसको इम्मीडिएटली अरेस्ट किया जाय। अगर आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं तो आप उस पूंजीपति को छूट देते हैं कि वह लाखों और हजारों मजदूरों को बेकार करके चला जाय। उन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, प्राविडेंड फंड का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए आप उन पूंजीपतियों को अरेस्ट कीजिये··· (**व्यवधान**)···

आप बैठिए। जनता रूल में क्या हुआ, आप भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। मैं जनता रूल को कोई ज्यादा समर्थन नहीं देना चाहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इन्दिरा जी की सरकार से कहीं ज्यादा अच्छी जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने आप की तरह राज नहीं किया। आज इस मुल्क के अंदर

इंडस्ट्रियल वर्क्स का, लैंडलैस पीजेन्ट्री का महंगाई का क्या हाल है यह सभी जानते हैं। आप क्यों छेड़ते हैं ? मैं कोई जनता सरकार का ज्यादा समर्थन नहीं करता हूं लेकिन आप से अच्छी सरकार थी। लोगों को यह दिन नहीं दखना पड़ा था कि गाय और सूअर की चर्बी आप डालडे में मिला कर लोगों को खिलाएं और लोगों के सामने असत्य बोलें। हम ने ऐसा नहीं किया था।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : जनता पार्टी के समय में चर्बी मंगाने का लाइसेंस दिया गया था, 37 इंडिविजुअल्स को लाइसेंस दिये गये। उस समय इन्होंने किसी को पकड़ा नहीं क्योंकि इन्होंने लाइसेंस दिये थे। आज ये लोग दोष हमारी सरकार पर लगाते हैं। यह प्रायश्चित करने का काम कर रहे हैं।··· (व्यवधान)···

श्री जगपाल सिंह : यह जो सवाल इन्होंने उठाया है अगर जनता सरकार में यह काम हुआ था तो उस समय आप भी अपोजीशन में वैसे ही बैठे थे जैसे आज हम लोग बैठे हैं, उस वक्त आप ने क्यों नहीं इस सवाल को उठाया था और मैं मांग करता हूं कि इस सवाल पर जुडीशियल एन्क्वायरी सरकार को मान लेनी चाहिए। आप जूडिशियल एन्क्वायरी मान लीजिए। मगर आप जूडिशियल एन्क्वायरी से भागते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इनके टाइम में टैलो आया, इनके टाइम में मिलावट की गई, हमारे टाइम में तो उसको पकड़ा गया।

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : The Resolution is not on tallow issue, let him conclude. You may note down the points, which he is mentioning and then you can reply to those points when you speak.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, हमारे राज्य में तो जहर भी आया था, लेकिन लोगों को मारने के लिए नहीं, उसका सही रूप से उपयोग करने के लिए। ··· (व्यवधान)·····मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि थोड़ा-सा अमेंडमेंट किया है, पहले होता यह था जैसी कि भारत सरकार की पॉलिसी थी, जो भी इन्डस्ट्रीसिक होती थी, उसको सरकार अधिग्रहण करके, उसको ठीक करके फिर कैपिटलिस्ट को वापस कर देती थी। इस प्रकार से करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार और इस देश के लोगों का इन पूंजीपतियों के द्वारा हुआ है। मैं मांग करता हूं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है कि किसी सिक इन्डस्ट्री को टेक ओवर करने के बाद, ठीक करने के बाद और मशीनें और नए उपकरण लगाने के बाद उस इन्डस्ट्री को कैपिटलिस्ट को वापिस किया जाए। भविष्य के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी सिक इन्डस्ट्रीज के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उनके खिलाफ सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। दुनिया के किसी भी कैपिटलिस्ट और डवेलपप्ड कन्ट्री के अन्दर इतनी इन्डस्ट्री सिक नहीं होती हैं, जितनी कि हमारे देश में इन्डस्ट्री बेकार हो जाती हैं। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार को इन्डस्ट्री के सिक होने की जानकारी और अध्ययन करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए। जो यह अध्ययन करे कि इन्डस्ट्री किन कारणों की वजह से सिक हुई है, पैसे की कमी क्यों हुई है, प्रोडक्शन में कमी क्यों हुई है और प्रोफिट कहां जाता है। उपाध्यक्ष जी, होता यह है कि प्रोफिट को एक्यूमलेट करते चले जाते हैं और सरकार से ज्यादा कर्जा लेते चले जाते हैं। कर्जे का पैसा रहता है और प्रोफिट को एक्यूमलेट करके एक नई इन्डस्ट्री खड़ी कर देते हैं। खास तौर से एशियाड के वक्त में फाइव-स्टार होटल की इन्डस्ट्री के बारे में अखबारों में एडिटोरियल में प्रकाशित हुआ था। कैपिटलिस्टों को विदेशी वर्ल्ड बैंक से भी छूट दी गई है कि वहां से पैसा लेकर हिन्दुस्तान के अन्दर फाइव स्टार होटल खड़ा करें। फाइव स्टार होटल को इन्डस्ट्री का दर्जा कर सबसे बड़ा नुकसान है और हमारे कल्चरल को खत्म करने के लिए है। एशियाड के दिनों में सारे होटल बन्द रहे और

वहां कोई विदेशी मेहमान नहीं आया। इसी सदन के एक माननीय सदस्य को फाइव स्टार होटल बनाने के लिए इजाजत दी गई है। स्टीफन साहब और कई माननीय सदस्यों की कोठियों को तोड़कर वहां फाइव स्टार होटल बनाया जा रहा है। उस होटल को बनाने में एक कंडीशन थी कि वह एशियाड से पहले उस होटल को तैयार कर लेंगे, लेकिन वह आज भी पूरा नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि उस होटल को इकानोमिक काम्पलैक्स बनाने की इजाजत दी या सरकारी दफ्तर खोलने की इजाजत दी, तो इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। मुझे बताया गया है कि दस-बारह करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया गया, सरकारी जमीन दी गई, लेकिन सारा पैसा बचाकर उसको अलग रख रहे हैं और वह होटल तैयार नहीं हो रहा है।

.....सरदार चरणजीत सिंह जी.....

सरकारी पैसे और सरकारी जमीन के इस प्रकार के उपयोग का मैं विरोध करता हूं।

आज देश में 52 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको भर पेट खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। ऐसे मुल्क के अन्दर इकानामिकली और साइंटिफिकली ऐसी इन्डस्ट्री लगायें, जो खेती से जुड़ी हुई हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि नार्थ इण्डिया के अन्दर गन्ने से जुड़ी हुई इन्डस्ट्री आपको लगानी चाहिए। चाहे आप बोर्ड पर लगायें, हैंडमेड पेपर पर लगायें, स्प्रीट पर लगायें, एल्कोहल के सही इस्तेमाल के लिए लगायें—इस प्रकार की ये सारी इण्डस्ट्री आप देहातों में लगा सकते हैं। सब्जी से जुड़ी हुई इण्डस्ट्री आपको लगानी चाहिए। लेकिन आप विलासिता आदि के सामान को बनाने के लिए लोन पर, कर्जा देकर, लाइसेंस देकर ऐसी इन्डस्ट्री लगा रहे हैं, जिनकी हमारे देश के लोगों को जरूरत नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि खेती से जुड़ी हुई इण्डस्ट्रीज को इस देश में इन्ट्रोड्यूस कीजिये। जो इण्डस्ट्रीज आज आप बड़े शहरों में कन्सेन्ट्रेट कर रहे हैं उनको देहातों में ले जाइये। देहातों में ले जाने से आज जो बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई और मद्रास में, हमारे मजदूर एम्पलायमेन्ट की तलाश में जाते हैं, जो वहां सड़कों पर झोपड़ियां बनाकर या पाइप्स में रहते हैं, वह समस्या खत्म हो सकती है। जब हमारे मजदूरों को देहातों में स्माल इण्डस्ट्रीज और बड़ी इण्डस्ट्रीज में काम मिलेगा तो वे शहरों की तरफ नहीं आयेंगे और इससे देहातों का भी विकास होगा।

पिछले साढ़े-तीन सालों के आपके राज में जितनी इण्डस्ट्रीज लगी, जितना प्रोडक्शन बढ़ा, उन सबका कन्सेन्ट्रेशन शहरों में हुआ। एक तरफ देश के लोगों की आमदनी गिर रही है, दूसरी तरफ अगर हिन्दुस्तान के साढ़े-बारह-सौ करोड़ लोगों की एसेट्स का जोड़ा जाय तो वह अकेले बिरला के ऐसेट्स से कम है—देश की जनता के साथ यह इन्साफ हो रहा है। हिन्दुस्तान के करोड़ों परिवारों की आमदनी साल में 1250 रुपये है, यह बात संसद में कई बार बतलाई जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के फाइव स्टार होटलों में इतना पैसा लगाया गया है जिसका लाभ देश की गरीब जनता को बिलकुल नहीं हुआ। इन फाइव स्टार होटलों में एक रात के ठहरने का किराया 2700 रुपये है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के एक परिवार की आमदनी, जिसमें पांच आदमी हैं, एक साल में 1250 रुपये हैं—यह अन्याय आपने देश की जनता के साथ किया है। इतना ही नहीं, जो आदमी 2700 रुपया किराये का देता है, अगर उसके सारे खर्चे को जोड़ा जाय तो 6000 रुपये के लगभग है लेकिन जिस आदमी की आमदनी एक साल में 1250 रुपये है, जिसके परिवार में 5 आदमी हैं, एक महीने में केवल 20 रुपये आते हैं। इस तरह के विकास को रोकिये, अन्यथा इस शुल्क में जो हालात पैदा होंगे उनको आप रोक नहीं पायेंगे। आज इस शुल्क में पंजाब की समस्या और दूसरी समस्यायें तो चल ही रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा भयंकर समस्या है वह है

गरीबी और बेरोजगारी की समस्या । 52 प्रतिशत लोगों के पास पीने का पानी नहीं है । वे बरसात का पानी इकट्ठा करके उससे कपड़े साफ करते हैं, उसको पीते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आज जो पूंजीवादी परम्परा चल रही है, पूंजीवादी को बढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको रोकिये । अगर आप इसको नहीं रोक पायेंगे तो हिन्दुस्तान में क्रान्ति हो जायेगी । मंत्री जी, अगर बदला श्रीमती इन्दिरा गांधी से नहीं लिया जा सकता है, राजीव गांधी से नहीं लिया जा सकता है, बैठे हुए मिनिस्टरों से नहीं लिया जा सकता है तो आपकी आने वाली जैनरेशन से बदला लिया जायेगा । जो इस मुल्क में आज जानवरों से भी बहतर जीवन गुजार रहा है, वह इसको बरदाश्त नहीं कर पायेगा । इस देश में आप जो फाइव स्टार कल्चर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की जनता इसको ज्यादा दिनों तक बरदाश्त करने वाली नहीं है । इस क्रान्ति को रोकने का रास्ता सोचें वरना आगे चलकर आप इसको रोक नहीं पायेंगे ।

आज आपके सामने एक समस्या यह है कि 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा आपने विदेशों से, इनटर नेशनल मानिटरी फण्ड, वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्थाओं से लेकर, इस देश के लोगों को कर्ज से दबा दिया है । यह 16 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हिन्दुस्तान की उस 52 प्रतिशत जनता पर, जो बिलो-पावर्टी लाइन है, खर्च नहीं हुआ है । यह बड़े लोगों पर, बड़ी इण्डस्ट्रीज पर, बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर, खर्च हुआ है । आपके बजट में आज भी 85 प्रतिशत लोग जो देहातों में रहते हैं उनके लिये 100 रुपये में से 30 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं । शायद 20 रुपये या उससे कम खर्च हो रहे हैं, जनता गवर्नमेन्ट ने भी 27 रुपये बड़ी मुश्किल से खर्च किये थे, ऐसी स्थिति में उनका विकास कैसे हो सकता है । मैं मांग करता हूं कि आने वाले बजट में देहात में रहने वाले 85 प्रतिशत लोगों के लिये आपके बजट का 85 प्रतिशत रुपया खर्च होना चाहिये और 15 प्रतिशत रुपया बड़ी इण्डस्ट्रीज वालों पर या जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाये तब इस देश के लोगों को न्याय मिल पायेगा ।

15.45 Hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : I support the resolution of comrade E. Balanandan. It is a most timely resolution. It will focus attention of the whole House and of the whole country towards the most chaotic and despotic situation obtaining to-day in our industrial world.

You know very well that the National Campaign Committee of Trade Unions is going to observe 4th December as the day against unemployment retrenchment and sickness in mills. To-day when we are debating industrial sickness, our comrade Homi Daji, Vice-president of AITUC is sitting on an indefinite hunger strike from 23rd November 1983 at Indore demanding immediate re-opening of Hope Textile Mills, which has been closed down. Six thousand workers have been rendered unemployed there. Bungling by the management is the reason for the Hope Textile Mills closing down. The workers are also fighting back They had occupied the factory on 3rd July. 1983. There has been a strike by 20000. textile workers in Indore, very recently. Even the INTUC came to the aid of the workers and joined the strike. And the individual hunger strike of Homi Daji continues.

The same thing happened in Pondicherry. You have been claiming that you are always getting sick mills and not working mills. In Pondicherry, you have nationalized a very good working mill ; but there also, our nationalized management bungled, and the workers there are all thrown out of employment. Life in the entire Pondicherry came to a standstill. But even then Government has not intervened.

The attack on the workers from the monopoly houses is becoming more and

more serious every day. This Government which is supposed to be the Government of the people, for the people and by the people sits tight doing nothing.

Even our Labour Minister who is sitting here said in Lok Sabha on 16th August 1983 that the closure of industrial units not due to any industrial dispute, rose from 350 in 1981 to 442 in 1982 ; the number of workers who lost jobs in 1981 was 37, 468 and in 1982—42, 101. This is the condition which Government of India accepts, but it does nothing about it. Our sick units in 1979 numbered 22,366 ; in 1982—28,360 upto June 1982. It is a rise of about 27%. In this matter, the big houses control every thing. How many big houses have fallen sick ? In 1979, the number of large houses which fell sick was 378 ; in 1981—422, medium : in 1979, 1013. It has come down in 1980-81 to 994 : small in 1979—20,975 and in 1981—25,342.

Why this sickness ? The Reserve Bank of India had made a survey of 100 large units falling sick in 1979. It has revealed very clearly about what is being done by big houses in collaboration with many persons here and there. Fifty-two units out of the 100 covered by the survey fell sick due to mismanagement and diversion of funds. They diverted funds from one unit theo ther; and the first unit fell sick 23 fell sick due to recession ; 14 due to faulty planning ; nine due to power cut and shortage of raw materials ; and only two due to labour disputes.

A story being circulated by the leaders of the ruling party here and there is that it is only due to the labour gangs going on strike here and there, that the units are becoming sick.

It is utterly wrong. The Government of India, the Reserve Bank has completely proved it to the hilt according to their own survey. Then they have been telling about a poor peasant who has taken a loan of Rs. 500 and who is not able to pay that loan. Immediately they will have to go to courts and do these things. Do you know that bank loans worth crores of rupees have been locked up in these sick units ? The bank loan locked up in 409 big sick units in December 1980 was Rs. 1324.47 crores ; in 1981, it was Rs. 1413.48 crores.

Now I will tell you what the Labour Minister has stated recently in Madras on 27.8.1983. He said,

> "Industrialists remain healthy while their units become sick."

He has also said that time has come for closer examination of the state of affairs in these industrial units ruled over by big empires and they remain healthy even when the units become sick. He described such industrial houses as a new class of *rajas* and *maharajas* who had emerged in place of old ones after independence. These industrialists have just 15-20 per cent of their stakes, or in some cases, even as low as 2.5 per cent. Those who have big stakes, besides workers and financial institutions, provide 70-80 per cent of the money.

Now, I quote another man perhaps the supporter of that party—Mr. Swarajpal. He is not our man. There was a lot of debate on him in this House. We may or may not agree with him but he has given a very big statement, a correct statement. He said," 11 big houses of India control Rs. 26,000 crores of government finance by investing only Rs. 140 crores. By investing only 2.5 per cent, these 11 big houses control cent percent." He has further said, "where does the money go ?" He has put a question. He said, "Rs. 25,000 crores of black money from these 11 big houses is lying in different banks of Europe and here in India our government of the people, by the people and for the people go before IMF for begging a paltry sum of Rs. 5,600 crores with must insulting conditions." This is the reality of India today.

What are the conditions of workers ? Very recently, you have nationalised 30 sick textile mills of Bombay. Is it a gimmick ? I do not know what for. Is it because you have been contemplating to hold elections in 1984 ? Is is planned to remove the sickness of the ruling party ? Why don't you nationalise all the textile mills of this country ? Why don't you nationalise the textile mills of Indore where a big struggle is going on ; and I am sure, our Labour Minister knows these things and what is going on there. The condition is really serious.

Gradually, as more days go on passing, we have a loss of more mandays, not due

to strikes, but due to lockouts. In 1977, there were 206 strikes, and the man-days lost due to strikes were only 10.72 lakhs ; in the same year, 1977, the lockouts were 191 and the mandays lost were 78.39 lakhs.

In 1980 the number of man-days lost due to 130 lock-outs was 46.9 lakhs, in 1982—in the year when you were ruling—the strikes came down to 29, the mandays lost was only 3.09 lakhs, but the mandays lost due to lock outs was 162.87 lakhs.

SHRI MOOL CHAND DAGA : In 1976 the percentage of mandays lost 12.76 or something ; you have to mention that also.

SHRI NARAYAN CHOUBEY : You want the emergency to be brought in this country ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Because you are quoting the figures you mention that years figures also.

SHRI NARAYAN CHOUBEY : In the meantime, the consumer price index was increasing. You see the condition. If 1960 was the base, 150, in January 1983 it was 449 and in 1983 September it was 554. And unemployment in 1981 was to the tune of 1, 78, 38, 100. In 1982 it has become 1,97;53,000, an increase of 10%. Unemployment has increased, but the placement is coming down. In 1981 there was a placement of 5,04,100 in industries and in 1982 the placement was 4,72,400—a fall by 6%. That is the actual condition. And in my State, what is the condition ? Shri Daga was asking about my State. It is very bad, in my State also. Several jute mills are under lock-out. Several workers, about 60,000 are employed in jute industry. Although we have been demanding nationalisation of jute mills, you will be glad to know that all the representatives of all the unions, AITUC, CITU, HMC, UTUC, HMP, and even INTUC of which you are a leader they are going to observe a continuous strike on the 16th January 1984 demanding nationalisation of jute industry; because the industry cannot be saved. They will take money from the banks, divert it to the other industries, but the industry will remain sick. And, the Government will not take any action. So, I say, let us take the case of Bengal Potteries. What is happening ? I am now told that the Union leaders are being asked to agree to retrenchment of workers, and that the Government will take action only then, that is, if the workers agreed to some retrenchment. This is what is being demanded by Shri Pranab Mukherjee, in a statement, I am told. You take INCHECK, National Rubber,—they are all in crisis. The only remedy is to take them over, nationalise them. But you have only given us words for the last three years and nothing else. Therefore, I put a question : What is the condition ? If a Kisan takes a loan and does not pay, if an agricultural labourer takes some loan, and it is not paid you arrest him. Here I find from your own statement, from the statement of the Government of India's Labour Minister that new type of Rajas and Maharajas are coming up now.

I demand, why action has not been taken even against a single man who was burgled public money. Many are flourishing in Delhi itself,but you are not taking any action. Many units are becoming sick, and they will continue to remain sick if you do not take action.

I support this resolution for this reason that you must take action to protect, the entire working class, as they are feeling helpless and their helplessness will turn into despair and then you will see, in this year as in 1982 which was the year of productivity, there will be maximum number of mandays lost. Due to strikes and look outs, by the big shots and by the big industrialists encouraged by our Government, which is for the people, of the people and by the people, those industries continue to remain sick. With these words I support this resolution, with the hope that you will take drastic action.

16.00 Hrs.

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री ई० बालानन्दन द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका कुछ कंडीशन के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि पिछले कई वर्षों से ताला बंदी, काम बन्दी और फैक्ट्रियों में स्ट्राइक होने से हमारी लेवर को काफी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से राष्ट्रीय उत्पादन उत्तरोत्तर

घटता जाता है। इसके कुछ कारण हैं। जहां एक तरफ अपने देश के प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं वहीं पर काफी हद तक हमारी गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्स के एक्जीक्यूटिव्ज भी जिम्मेदार हैं। श्री बालानन्दन जिस पार्टी से विलांग करते हैं, इनके मित्र भी काफी हद तक लॉक आउट करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमने पिछले तीस-पैंतीस सालों में जो लेवर में कल्चर क्रिएट करना चाहिए था, वह नहीं किया है। जिस पार्टी को सी० पी० आई० के लोग विलांग करते हैं वे उसमें हिस्सा लें तो क्या नतीजा होगा? इसलिए, हमें अपने देश में श्रमिकों में राष्ट्रीय भावना जगानी चाहिए।

हम लोग साऊथ कोरिया गए थे। हम वी० आई० पीज थे और हमारे साथ स्पीकर साहब भी थे। हम लोग वहां के शिपयार्ड और इलैक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्री आदि देखने गए। उनके पावर हाउस में गए। उनके मिनिस्टर और चेयरमैन भी हमारे साथ थे। किसी भी लेवर ने हमारी और स्पीकर साहब की तरफ नहीं देखा। मुझे याद आता है हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान कामर्स मिनिस्टर श्री विश्व-नाथ प्रताप सिंह ओवरा थर्मल पावर स्टेशन गए। वहां भयंकर आग से काफी नुकसान हुआ था। उनके लिए लिफ्ट पर चढ़ना मुश्किल हो गया। पांच हजार से अधिक मजदूर उनके अगल-बगल में इकट्ठा हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश में काम करने का वातावरण होना चाहिए। साऊथ कोरिया में 16 घंटे काम करते हैं और इतवार की दो छुट्टी लेते हैं। हमारे यहां ईमानदारी से आठ घंटे भी काम नहीं करते। जो अपने आपको लेफ्टीस्ट कहते हैं और बड़े वर्कर्स की बात करते हैं, इन्होंने देश में बड़ा ही खराब वाता-वरण तैयार किया हुआ है। इसलिए, मेरी अपील है कि हम संजीदगी से विचार करें। ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे हमारी प्रधान मंत्री ने जो देश को आगे बढ़ाने का काम हाथ में लिया है, उसमें सफलता मिल सके। हमारी सरकार की पालिसी अनाउंस करने के बाद कि पांच हजार रुपए तक कोई जमानत नहीं ली जायेगी, हिन्दुस्तान में कोई बैंक हरि-जन-आदिवासियों, लघु और मार्जिन कृषकों को लोन नहीं देगा। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जो सिक मिल कर देते हैं और एक जगह का पैसा दूसरी जगह ले जाते हैं, उनके साथ कोई कड़ाई नहीं की जाती है। यही नहीं ट्रकों की जनता पार्टी के राज में इतनी कीमत बढ़ गई थी कि एक एक चेसिस पर 60,000 रु० का ब्लैक था और पैसे वाले लोगों ने उस समय बैंकों से मिल कर करोड़ों रु० कमाया। एक ट्रक पर 60,000 रु० का ब्लैक था। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी घपला चलता है। ठीक है कि हमने फिक्स्ड इकोनामी मानी है लेकिन उन पर कंट्रोल करना तो सरकार का फर्ज है जबकि उनमें बैंकों का पब्लिक मनी लगा है। यह बात ठीक है कि केवल 140 करोड़ रु० लगा कर उन्होंने 2,600 करोड़ रु० देश का लिया है इसलिए उनके खर्च पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उनके दफ्तरों में जाइये और खर्चे देखिये, शादी, विवाह में होने वाले खर्च को देखिये किस तरह से अनापशनाप खर्च किया जाता है। कहां से आता है यह सारा पैसा? इसका सारा पता लगाया जा सकता है और खर्च पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है जिससे यूनिटस सिक न हों।

पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को आपने अटोनामस बनाया है ताकि उनकी व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन हो उल्टा रहा है। जितने मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर और ऐग्जीक्यूटिव्ज हैं वह पुराने जमाने के राजा, महाराजाओं से बढ़ कर शान शौकत से रहते हैं। उनकी कमाई कैसे होती है? जो उनकी तरफ से ठेके दिये जाते हैं, यद्यपि उन पर सरकार के नियम लागू नहीं होते, लेकिन ठेका अवार्ड करने के पूर्व परसेंटेज बंधा हुआ है। सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिये प्रधान मंत्री ने 3 रोज पहले पब्लिक सैक्टर के परफारमेंस पर असंतोष जाहिर

किया है और कहा है कि उनके मैनेजमेंट में सुधार हो। इसके अलावा हमारी प्लानिंग में भी सुधार होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के लिये लाइसेंस देते हैं तो विचार करना होगा कि क्या वहां बिजली और री-मैटीरियल है? अगर नहीं है तो भले ही कितना बैकवर्ड इलाका हो जहां इंडस्ट्री लग रही है, वह नहीं चल पायेगी। एक बहाना मिल जाता है पूंजीपतियों को कि हां बिजली और रा-मैटीरियल नहीं मिला इसलिये यूनिट सिक हो गई। इसलिये उद्योग विभाग को देखना चाहिए कि जब लाइसेंस दें इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाय। वरना कोई लाभ होने वाला नहीं है। होता क्या है कि बड़े-बड़े अधिकारियों से मिल कर पूंजीपति लोग इस तरह के काम करा लेते हैं जिनमें सरकारी पैसा डूबने लगता है। इस तरह की बातों को रोका जाय। मथुरा रिफाइनरी से पाली प्रोफलीन निकलने वाला है जिसका लाइसेंस हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार लेना चाहती है। लेकिन उसको नहीं मिल रहा है और अधिकारियों की सांठगांठ के कारण उसको गुजरात ले जाने की बात चल रही है। बैकवर्ड इलाका जरूर देखें, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाय कि जहां उद्योग दे रहे हैं वहां वांछित चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं ताकि पूंजीपति बहाना बना कर के सरकारी पैसे को हड़प न लें।

श्रम मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान दिलाता हूं कि आज 30,000 ईंट भट्टे बन्द हैं जिसके कारण 50 लाख मजदूर बेकार हैं। यद्यपि इनमें 8 महीने ही काम होता है, लेकिन जब कभी 5, 10 हजार आर्गेनाइज्ड मजदूरों की बात होती है तो उसके लिये काफी शोर शराबा होता है। लेकिन आज 50 लाख गांव के गरीब, हरिजन, आदिवासी मजदूर बेकार बैठे हुए हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

पिछले कई महीनों से यह आवाज उठ रही है कि गवर्नमेंट को यह भी देखना चाहिए कि वह कोई ऐसे बिल या कानून लागू न कर दे जिससे हम जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं वह बैठ जायें। आज ईंट-भट्टे वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बांडेड लेबर एक्ट, बोनस एक्ट, प्राविडेंड फंड एक्ट, इंटरस्टेट एमीग्रेंट एक्ट लागू कर दिया। यही नहीं कई विभिन्न राज्यों ने भी यह दिखाने के लिये कि हम लेबर हितैषी हैं कुछ काम किये हैं। मेरा कहना है कि लेबर का कल्याण कीजिये, लेकिन आप उनका क्या कल्याण करेंगे जिन 50 लाख लेबर के लोगों को आपने घर में बिठा दिया है। आप जब कोई कानून बनायें तो सब तरीके से विचार करके बनाइये।

श्रम मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनका बड़ा कृतज्ञ हूं कि इन्होंने अभी हाल ही में एक कमेटी में कहा कि हम शीघ्र ही पार्टी कमेटी बुलायेंगे जिसमें ईंट भट्टे के प्रतिनिधि भी होंगे और सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। मेरा कहना यह है कि जब 50 लाख लोगों का काम बन्द हो जाता है तो इससे नेशनल लास होता है।

अभी जनता सरकार के एक सदस्य गला फाड़कर कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि उनके जमाने में हमारा औद्योगिक उत्पादन—1.4 हो गया था, यह तो हमारे प्रयास से हमारी सरकार के 1980 के बाद सत्ता में आने पर यह उत्पादन बढ़ा है। कहीं 10 परसेंट बढ़ गया, कहीं 8 परसेंट और 6 परसेंट बढ़ गया है यानी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

हमें खुशी है कि हमारे श्रम मंत्री इस सैशन में मजदूरों के लिये ग्रैचुइटी बिल में कुछ अमैंडमैंट करने जा रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों में भी कई ऐसे काम किये हैं। इसीलिये यह बात सही है कि आज पूरे देश में औद्योगिक शांति बनी हुई है। हमारे विरोधी भाइयों द्वारा हौआ खड़ा किये जाने के बाद भी देश में स्ट्राइक कम हुई है और आज ला एंड आर्डर की प्राब्लम औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। यह सारा क्रैडिट श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को जाता है। इनकी बिगाड़ हर चीज पर है।

इसलिये आज हमें कोई बात किसी आलोचना की दृष्टि से ही करनी चाहिये। हमारे पिछले भाई ने बोलते समय कहा कि सारा काम इन्दिरा सरकार ने चौपट कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिये मैंने कंडीशन शब्द कहा था, कि इन्होंने सदन का और देश का ध्यान इस ओर खींचा है। आज के इस निर्माण के युग में ले-आफ, स्ट्राइक और लाक-आउट नहीं किया जाना चाहिये। इन्होंने अभी भी सरकार पर आक्षेप लगाये हैं, लेकिन मैं दूसरा पहलू कह रहा था कि हम सब जिम्मेदार लोग हैं, देश में हिंसक आन्दोलन चलाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन बीजापुर में बना था, वहां बड़ी शांति से काम चल रहा था, अगर मजदूरों का शोषण कहीं होता हो तो उसे रोकना चाहिये लेकिन हमारे सी०पी०एम० और सी०पी०आई० के लोग वहां गये और उनकी पार्टी के लोगों ने वहां मार-पीट कराई इस तरह से बहुत से लोगों को वहां से निकाला गया। इसी तरह हिन्डालकों में भी इन्होंने हौआ खड़ा किया और वहां से भी 150 मजदूर निकाल दिये गये। हमें कोई रचनात्मक विचार करना चाहिए कि किस तरह से समन्वय करें जिससे देश में इंडस्ट्री ठीक चलें, देश आगे बढ़े।

सरकार को भी निश्चित बातों पर सोचना पड़ेगा कि जिन पूंजीपतियों ने देश का रुपया लेकर निजी उद्योग-धंधों में लगाया है, उन्होंने उसका कितना उपयोग किया है। यह बात सही है कि आज गांव का किसान, मजदूर सरकार से अपेक्षा करता है कि यदि उस पर बकाया है तो उससे जमीन के लगान की वसूली की जाती है, लैंड से रैवेन्यु की वसूली की जाती है, अगर वसूली नहीं होती है तो उसको हथकड़ी लगा कर बन्द किया जाता है। इसलिये आज कोई कारण नहीं है कि हमारे सरकारी खजाने का रुपया जिन शर्तों पर लोगों ने लिया है अगर वह उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको भी हथकड़ी लगाकर बन्द किया जाये तभी लोगों में संतोष होगा। इससे देश में बड़े छोटे का भेदभाव भी नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ कंडीशन के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि निजी क्षेत्र के तमाम कारखाने, खासतौर से जिनके बारे में कामरेड बालानन्दन ने प्रस्ताव रखा है, इस प्रकार के संकट में गुजर रहे हैं, ले-आफ, क्लोजर और लाक-आउट से सफर करते हैं, इससे हमेशा तमाम मजदूरों के सामने भीषण संकट पैदा हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निजी क्षेत्र के कारखानों में होती है।

जब यह स्थिति आती है तो तमाम हमारे मजदूर भाई बेकार हो जाते हैं और उनके सामने घोर आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। प्राय: जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनके ये कारखाने होते हैं वे मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं और जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठती है, जब मजदूर अपने हक की मांग करता है, जब मजदूर चाहता है कि उसे न्याय दिया जाय, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाये जाते हैं।

स्ट्राइक तभी होती है जब वहां का मजदूर वर्ग यह महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जब अन्याय के खिलाफ वह आवाज उठाता है तो उसे कुचलने और दबाने के लिए पूंजीपतियों के द्वारा ये हथकंडे अपनाये जाते हैं। इसलिए सरकार का विशेष रूप से उत्तरदायित्व है, कि जब कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो पूरी स्थिति की ठीक से विवेचना करें, उसकी समीक्षा करें और यदि ईमानदारी से उसकी विवेचना की जाय, उसका विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि अधिकांश पूंजीपति जो शोषण के लिए मजदूरों को दबाना चाहते हैं और अन्याय करना चाहते हैं वे अपनी शोषण की प्रक्रिया को जारी रखने के

लिए यह क्लोजर, लाक आउट और ले आफ वगैरह करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके ऊपर एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाय।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार इस काम को करने में बहुत हद तक विफल रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार बिलकुल इसे करना नहीं चाहती। लेकिन जो कुछ भी सरकार ने आज तक किया है उसमें कोई अधिक सफलता नहीं मिली है। कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि मिलों का टेक ओवर हुआ है, सरकार ने उनका अधिग्रहण किया है, उसके बाद उन मिलों पर जो बकाया कर्जे थे उनको वापस किया गया है, कारखाने का आधुनीकरण किया गया है और कारखाना जो पहले चलने की स्थिति में नहीं था, सरकारी व्यवस्था के के बाद उसको चलाया गया है। कुछ दिनों तक कारखाने को चलाने के बाद और उसका आधुनीकरण करने के बाद जब कारखाना ठीक स्थिति में आ जाता है तो कभी-कभी यह भी देखा गया है कि वह कारखाना फिर पूंजीपतियों को वापस कर दिया गया है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार को कतई यह काम नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप कारखाने का अधिग्रहण करते हैं और उसको ठीक करके फिर उसी पूंजीपति को लौटा देते हैं तो निश्चित रूप से उससे वह मुनाफा कमाते हैं और पुरानी शोषण की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि जब कभी आप किसी कारखाने का अधिग्रहण करते हैं तो उस कारखाने को फिर वापस मत लौटाइए। कटिहार में एक जूट मिल है। राज्य सरकार ने उसका अधिग्रहण किया था। जब कारखाना ठीक हो गया तो फिर उसे पूंजीपतियों को वापस कर दिया। पूंजीपतियों ने मजदूरों को तबाह कर दिया। उनकी तमाम न्यायोचित मांगें नहीं मानीं, उन्हें जो हक मिलना चाहिए वह नहीं दिया। जब मजदूरों ने हड़ताल की तो वहां पर वही लाक आउट वह कर देते हैं या क्लोजर कर देते हैं। इस तरह के हथकंडे वे अपनाते हैं और साथ-साथ मजदूरों के ऊपर बर्बरतापूर्वक सरकारी तंत्र का सहारा लेकर अत्याचार करते हैं, उनको कुचलने की साजिश करते हैं। पुलिस बुला कर लाठी चार्ज करवाना, लोगों को गिरफ्तार कराना, उन्हें घरों से निकाल कर बाहर कराना, ये सारे काम वह करवाते हैं। मैं खुद वहां कटिहार गया था और मैंने सारी चीजें देखीं कि किस प्रकार की घटनाएं हुई। मजदूरों ने वहां पूछा कि जिस मिल को सरकार ने अधिगृहीत कर लिया था उसको उसने वापस क्यों किया? वे चाहते थे कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इसी प्रकार स्वदेशी काटन मिल का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। जनता पार्टी के समय में सरकार ने उसका अधिग्रहण किया था। अब वे कारखाने धीरे-धीरे लगभग ठीक हालत में आ गये हैं तो अब फिर से यह कोशिश चल रही है कि इसे उन्हीं पूंजीपतियों को वापिस कर दिया जाय जबकि मजदूर और जितने भी जनता के हितैषी व्यक्ति हैं वह यह चाहते हैं कि उन कारखानों का राष्ट्रीकरण किया जाय। लेकिन सरकार हर छः महीने के बाद एक नोटिफिकेशन करके उसके अधिग्रहण का समय बढ़ाती जा रही है, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है। इसलिए मेरी जोरदार मांग है कि स्वदेशी काटन मिल समूह का अधिग्रहण सरकार ने किया था, राष्ट्रीयकरण किया जाय। अगर यह राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो यह 'मजदूरों' के साथ घोर विश्वासघात होगा। सरकारी खजाने से पैसा लेकर मिलों को ठीक करने के बाद और फिर उनको पूंजीपतियों को वापिस कर देना देश की जनता के साथ घोर अन्याय है। इस प्रकार की नीति का मैं विरोध करता हूं। उन तमाम कारखानों का जिनको सरकार ने अधिग्रहण किया है, उनका राष्ट्रीयकरण करने की मैं मांग करता हूं :

चीनी मिलों के साथ भी यही बात होती है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ज्यादातर

मिलें निजी क्षेत्र में पूंजीपतियों के हाथ में हैं। वहां स्थिति यह है कि वे उन मिलों को मोडर्नाइज नहीं करते हैं आधुनिकीकरण नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद कारखानों का उत्पादन घटा देते हैं, जिससे मजदूरों को उन का हक नहीं मिलता है। तमाम मिलों के अन्दर 6-6, 8-8 महीने का मजदूरों का वेतन बकाया है। हमारे क्षेत्र में एक धुंधली चीनी मिल है, जहां पर कि मजदूरों का 6 महीने का वेतन बकाया है। इसी प्रकार बगल में एक सिस्वा मिल है, जहां पर आन्दोलन हुआ था। वहां पर तमाम मजदूरों और किसानों को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया था। वहां पर भी मजदूरों का 6-8 महीने का वेतन बकाया है। वहां पर लाठी चार्ज और पता नहीं क्या-क्या चीजें हुई थी। वहां एक मिल सरकार के अधिग्रहण में है और दूसरी पूंजीपति के हाथ में हैं। जो मिल सरकार के हाथ में है, वहां भी मजदूरों का बकाया नहीं मिल रहा है और जो पूंजीपति के हाथ में हैं, वहां पर तो शोषण हो ही रहा है। वहां तो पैसा मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। सिस्वा मिल का पहले अधिग्रहण हुआ था, फिर बाद में उसको वापिस कर दिया गया। आज फिर यह मांग हो रही है कि उस मिल को टेकओवर किया जाए और उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह एक विचित्र-सी स्थिति है कि एक बार मिल को टेकओवर करके, ठीक करके फिर पूंजीपतियों को वापिस कर दिया जाता है। जब वह मिल पूंजीपतियों के हाथों में जाती है, तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि जिन चीनी मिलों को टेकओवर किया गया है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। अपने हाथ में रखा जाए, उनको पूंजीपतियों को न दिया जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जहां कहीं पर भी मजदूरों का पैसा बकाया है, उन मिलों को टेकओवर किया जाये और अपने नियंत्रण में रखा जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा ले-आफ निजी क्षेत्र के कारखानों में होता है, लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र को काफी बढ़ावा दे रही है। वैसे 1947 में आजादी के बाद से ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। पूंजीपतियों ने इस देश की जनता का शोषण करके अपनी पूंजी को अथाह-समुद्र की तरह से फैला रखा है उसका वे तरह-तरह से नाजायज लाभ उठाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं और न्यायोचित निर्णयों पर भी रोक लगाते हैं। जनता के हक में निर्णय न होकर पूंजीपतियों के हक में निर्णय होने लग जाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना बन्द किया जाए। अगर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम बन्द नहीं किया गया तो इस प्रकार के शोषण की व्यवस्था जारी रहेगी और मजदूरों का शोषण होता रहेगा और हम उसको रोक नहीं पायेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम बन्द किया जाए और उनके ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाए। उनके मन में यह भय पैदा किया जाए कि मजदूरों का शोषण करके वे अधिक दिनों तक नहीं चल सकते हैं। आज ऐसे भी पूंजीपति हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है। बाहर के पूंजीपतियों को भी बुलाने की बात चल रहा है स्वराजपाल का बहुत ही मशहूर उदाहरण है। आज देश के पूंजीपति ही जनता और देश के गरीब मजदूरों को तबाह कर रहे हैं। यह सरकार की कैसी योजना है, समझ में नहीं आता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ले-आफ, लाकआउट और क्लोजर जैसी स्थिति पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको पूंजीपतियों को बढ़ावा देना बन्द करना पड़ेगा।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गोरखपुर में एक खाद का कारखाना है। जो काफी पुराना हो चुका है। खाद का कारखाना, जो कैमिकल्स के कारखाने होते हैं, इनका जीवन

नम्बा नहीं होता है। बीस साल से तीस साल तक इनका जीवन होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार जल्दी ही उस कारखाने का एक्सपेंशन नहीं करती है, उसका विस्तार नहीं करती है, तो वह इन्डस्ट्री भी सिक हो जाएगी। सिक होने का मतलब यह है कि हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। एक तो पहले ही देश में भीषण बेरोजगारी फैली हुई है। हमारे देश के नौजवान बेरोजगारी की वजह से तबाह हो रहे हैं। वहां जिनको रोजगार मिला हुआ है, यदि वह इन्डस्ट्री सिक हो गई, तो वे लोग भी बेरोजगार हो जायेंगे। इस प्रकार देश में बेरोजगारी की बढ़ोतरी ही होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गोरखपुर में जो खाद का कारखाना है, जो काफी पुराना हो चुका है, उसका तत्काल विस्तार किया जाए। इसके बारे में मैंने उर्वरक मंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जांच कर रहे हैं और कार्यवाही करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जो माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से उर्वरक मंत्री जी तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं और उनका भी सहयोग लेना चाहता हूं, ताकि उस खाद के कारखाने का सिक होने से पहले विस्तार किया जाए, ताकि मजदूर बेरोजगार न हों।

इन्हीं शब्दों के साथ में कामरेड बालानन्दन के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) : Mr. Chairman, Sir, many hon Members have spoken on the question of industrial sickness and its consequences. Much more will be said later also on this aspect. Industrial sickness is a product of industrial revolution The quest for affluence and matreial advancement also give us illness easily in various industries. Many studies, seminars, committee reports and other literature have thrown light on various causes, effects, problems and solutions to the growing industrial malignancy in the economic system like ours. Lot of literature is published on the subject and many seminars and studies are being conducted all over India to highlight the problem of industrial sickness. When we examine the impact of industrial sickness in our socio-eoonomic growth and equitable distribution of wealth this pre-occupies a paramountcy in our mind. Therefore, the debate and discussion, of course, highlight the problems of industrial sickness and show how it retards or arrests the growth of the nation.

Now, in the resolution presented by the hon. Member, has two parts. The genesis of the first part is the industrials sickness and the second part relates to the consequences on labour. You are fully aware that there are basically four factors of production-land, labour, capital and management.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Now, it is out moded. There are only two factors of production.

SHRI XAVIER ARAKAL : No. There are four factors of production.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Let him have his own theory.

SHRI XAVIER ARAKAL : Now, these are the four basic factors of production which give an economic growth or stability in any nation. Of course, as my hon. friend just now mentioned, there are various inputs and other classic factors of production, etc. I would say "classic" as every economic student must have learnt that it is a classic economists classification of production.

In this resolution, the emphasis has been given to lay-offs, lock-outs and closures. Of course, it is a factor. But it is not the sum total of the causes and effects of the problem. It has to be viewed in a larger way to have a comprehensive imagination as well as scheme to solve it. That is why, I am emphasising on that aspect of the whole. Various studies have revealed and the hon. Minister of State for Finance has also said in reply to an Unstarred Question that 52% of the sickness is due to the fault in management or mismanagement.

This is a vital aspect, a factor, which we should consider, how and why. The basic element or cause for the industrial sickness is managerial problem.

The next important aspect or cause is the lack of finance. Labour is a marginal factor in the cause of this industrial sickness. of our country.

Now, the basic question which comes to my mind is ; Can a nation like ours, where the capital is so scarce, where the skill is so dear and valuable, afford it to be wasted or unutilised in the manner in which it is being done in our country ? This is the basic issue which we have to think aloud. Can a socialist country like ours afford it ? If we want to have an economic growth, to remove poverty and unemplopment, we have to make the best use of all these factors because the basic philosophy is the greatest happiness of the greatest number in our national endeavour. Therefore, the Government must come forward to say what are the measures they are taking to remove of diminish the difficulties of managerial, capital and labour problems.

I was astonished to note some of the facts. In 1979, there were 345 large and 20,326 smallscale sick units and, in 1980, the figure has gone up to 767 large units, 1,759 medium units and 23,255 smallscale units. This highlights the seriousness of the problem which we are facing today. A further study has revealed that institutional credit "locked in" these units, in December, 1980, amounts to Rs. 2064.27 crores. The break up of this figure is that banks alone account for Rs 1802.24 crores, IDBI-Rs 140.06 crores, IFCI-Rs 121.79 crores, if you add ICICI which has given Rs 58.36 crores, it comes to Rs 2122.63 crores.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Is it the total investment ?

SHRI XAVIER ARAKAL : I am coming to that.

Can the Government say that this much scarce capital is not wanted ? What does the Government propose to do in regared to this institutional credit which is locked in these various sick units ?

In West Bengal alone, they have one-fourth of large-scale units as sick units that is, 106 units and also 7,826 small units are sick in West Bengal. What is the reason ? Is it the political climate there ?

SHRI CHITTA BASU : What is the politics there ?

(*Interruptions*)

SHRI XAVIER ARAKAL : This is something astonishing that where a Socialist or Communtis Government is in power, they have these many sick units. What is the cause for that ? In West Bengal, as the Minister for Commerce and Industry of West Bengal Government, Mr. Bhattacharya has on 22nd June, 1983 said that he is going to sell various companies to the private sector. He said that 26 units are going to be sold to the private sector. Why hashe said so ? 12 units belonging to the State Government are going to be sold to the private sector and five units of IRCI and nine jointly-owned companies are also going to be sold to the private sector. This is something which we have to take note of because the Government there has failed to create a climate for industrial growth and to reduce the iudustrial sickness.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : As if you are reducing in your State :

SHRI XAVIER ARAKAL : The West Bengal Government has the maximum mandays lost as well. This is, of course, a part of your question relating to the factors of production.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : It is part of general sickness.

SHRI XAVIER ARAKAL : It is not a part of general sickness. It is peculiar to Bengal. One-fourth of the major industrial sick units are in Bengal. My Hon. friend comes from Jammu & Kashmir.

SHRI CHITTA BASU : So what ?

SHRI XAVIER ARAKAL : I am very much concerned. It is the capital belonging to the poor of this nation which has to be utilised for proper, efficient production and for production purposes.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : What about Orissa, U.P and Kerala ?

SHRI XAVIER ARAKAL : Kindly allow me to elaborate. It is a very important subject. I hope you are patient enough. Outstanding dues from various sick units is to the time of Rs.1,479 crores. It was a

year back but now it is Rs.1,753 crores that is, an increase of Rs.256 crores a year, 'outstanding dues'.Where do the moneys come from ? Who is accountable for that ? Take the case of public investment. I am taking one part low to illustrate the point. That is public investment and industrial sickness becasue other Member also should have their say on other areas. It is said that capital employed is Rs.21,865 crores in 1981-82 and the gross profit is Rs.2,674 crores that is, only 12.23%.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Is it relating to total of public sector investment ? It is at variance with the figure quoted by our Hon. Minister of Finance.

SHRI XAVIER ARAKAL : I am giving my reference from BPE Vol. I. The turn-over is some Rs. 36,443 crores in 1981-82 that is; only 13% inrcrease. If 12.23% is the Profit and the turn-over is only 13%, can we visualise a economic growth in harmony with our national aim ? If that is not achieved, certainly proportionately it will be going down as sick units. We have no definition of a 'sick unit'. The Reserve Bank has said that if there is a cash loss for a year and in the next two years if the cash loss is continued and the debt equity ratio is worsening then that is a sick unit. If you take the case of public sector, I am afraid many have to be declared as sick units.

An aspect which has to be borne in mind is that Government investment has increased manifold. As on 31-3-1982 Government investment in various industries amounted to Rs. 22,504.43 crores in terms of value of gross block. From 1977-78 to 1981-82, Government has invested Rs. 14,053.23 crores, in a five-year period. What is the cash loss ? I am giving these figures so that the House will understand and appreciate the seriousness of this problem. It is alarming. In 1982-83 the cash loss alone is Rs. 642.88 crores. In 1981-82 it was Rs. 537.72 crores. If you take the accumulated losses, it will be an astronomical figure. Twelve units alone have incurred a loss of Rs. 689.37 crores. This is also from the BPE report. In respect of non-petroleum institutions it is better not to say anything. This is the state of affairs in many of the public undertakings in our country. My question is for how long a nation like ours can afford this. In 1980, if I remember right, under the Chairmanship of the State Minister for Industry a Committee was constituted. There is no dearth of Committees and Committee reports. What I as a Member of Parliament, as a taxpayer and as a humble citizen of this country would like to know is for how long we can continue with this malady or malignance in public sector, for how long we can allow this capital to be idle and ununtilised. What about the implementing aspect of various Committee reports ? What has government done there ? This is a matter of serious concern and our Prime Minister has time and again expressed her anxiety. I am sure there are very good points as well. Many public sector undertakings have shown profit and I do appreciate and congratulate them. At the same time we cannot forget or ignore the dark side of this because our ultimate aim is to have a greater growth rate in the industrial sector. Today, we are proud ; our nation is one among the major industrial nations of the world but it can be far, far better also.

I will now come to the solutions. I am sure the House is anxious to know as to what are my humble solutions. I am suggesting four corrective measures. One is self-discipline. This is imperative in any socialist country .....

PROF. SAIFUDDIN SOZ : That is a Gandhian principle.

SHRI XAVIER ARAKAL : Whatever principle it is, it is upto you.

I had the opportunity to visit recently the Republic of Korea, a country which was far, far below in per capita at the time of their independence. Now that country is one of the most industrialised and advanced countries. How did they progress ? The discipline they have shown is something which has to be congratulated. ..... *(Interruptions)*

What is worng with these people ?...

SHRI M. M. LAWRENCE : I want to know whether it is North Korea or South Korea.

SHRI XAVIER ARAKAL : That is the basic requirement we need self-discipline in this area.

The second thing is the too much dependence on the Government and the Government also has a super arm over all the activities of the institutions. The numerous regulations, Acts, Notifications and what not they are all curtailing the initiative, self-reliance and independence of various institutions. They depend on the Government for everything. That dependence has to be removed with a drastic surgery in this area.

Another suggestion which I have in mind is that after all this accumulated wealth, this idle wealth is the wealth of the nation which we can ill afford to be wasted. My suggestion is that the Government, by an amendment of the relevant Act, must take over these sick units without any compensation. I have been demanding this for a long time, time and again in this House ...

SHRI M. M. LAWRENCE : We support you.

SHRI XAVIER ARAKAL : We as a nation should take over the assets of these sick units and without compensation and for a considerable period of time and the value of the sick unit should be credited to he National Savings Fund. If we adopt such a drastic measure, may of the illnesses can be removed in a better and efficient manner.

My fourth suggestion is that there is now very little commitment on the part of the labour in running these institutions, whether it be sick unit or a healthy unit. Unless there is a commitment, it is not possible to have better relations. How to create it ? How to create that atmosphere, that attitude among the labour as well as the management in the running of the firm ? Unless there is a financial risk involved, it is not possible. Therefore, I have one suggestion if the Government is willing to consider it. That is, the provident fund and bouns should be converted into the equity shares of the firm. If we take a decision towards that end, it will have far-reaching consequences in various aspects which, on some other occasion, if the time permits, I will elaborate.

My last suggestion is that the Government should adopt a policy to revive the sick units rather than allow any new units in the same area and sector. I am sorry to say that this is not done properly, efficiently and, therefore, there is a mushrooming of units in the same sector causing a lot of economic loss.

Sir, this Government should insist on reviving rather than allowing to have any new unit in the same area. That will be a great help towards reducing or diminishing the industrial sickness.

I am citing two seamples in different classifications.

In that respect, I have been asking here—I have been demanding under Rule 377 and through supplementaries—to take over Bennv Company in Cochin and to run it. (*Interruptions*) I would like to know from Government that since that is a viable unit which has been locked up by the management, why not they amend the Industries Regulation Act of 1951, if necessary, and to take over such unit, make it a model unit and give it to the nation ? That will be a great help.

I have been asking about one unit—Auto Friction—in Trivandrum and I have written so many letters to both the Finance Minister as well as the Industry Minister asking for help. They are not positive in their approach. They have wasted so much of money. Do yon want to give concessions in the matter of tax ? Sir, I am sorry to see the attitude shown by the bankers or by some other quarters. Had they shown a positive attitude, they could have revived that unit which could have done a lot of progress in this area and sector.

These are my suggestions. I do support the Resolution moved by my hon. friend, Shri Balanandan. I request that my suggestions, taking into account the various aspects of production in the area, should also be taken into consideration as an amendment to his Resolution.

MR. CHAIRMAN : Mr. Chitta Basu. Before you speak, I want to say that the time for this Resolution runs out at 4-56 hours. Still, a large number of party members have not yet spoken. So, at about that time, we will have to take the sense of

the House whether you wish to give more time to this Resolution.

SHRI M. M. LAWRENCE : The time may be extended.

MR. CHAIRMAN : After Mr. Chitta Basu speaks we will ask the House about extending the time for the discussion. Shri Basu, you may continue.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I rise to support the Resolution moved by my friend Shri Balanandan. It is not a question of extending the time for this Resolution.

16.54 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

As a matter of fact, the hon. Member deserves congratulations on account of the fact that, by this Resolution, the House has the opportunity of discussing a very important and vital aspect of our industrial life. Everyone of us is very much eloquent about the industrial development of our country. But, many of us are ignorant about the diseases which have already crept into the industrial structure of our country. The industrial sickness is the greatest of that kind of disease that has crept into our industrial structure today. My hon. friends were very much enthusiastic in condemning of Government of West Bengal by simpli fying the fact that the number of the sick industry of the country, if we calculate statewise, is the largest in that State. This provides an important insight about the industrial structure of our country.

Sir, I have got no time to take up such matters. Here it is clear that capitalism in our country has reached a stage of crisis and that this industrial sickness is manifestation of that along with others. Therefore,...

MR. DEPUTY SPEAKER : The time for this resolution has already been extended upto 5.30 p.m. but there are still many hon. Members who want to speak on this resolution. So, the discussion cannot be completed by 5.30 p.m. Is it the pleasure of the House that we extend the time by one more hour and continue with it next time also ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY SPEAKER : So, we extend the time by another one hour and carry it to next time.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I want only to urge upon the Minister of Industry to take note of the enormity of the problem. The enormity of the problem has been correctly identified by my distinguished friend when he quoted the figures of the Reserve Bank of India and all available data. In short I am to just mention that as on June, 1982 there were 28,360 units which are taken to be sick and the total amount of the bank capital involved is more than Rs. 2,000 crores. These two very simple facts makes clear as to the enormity of the problem.

Sir, I don't say that Government is not aware of the problem. Government is very much aware of the problem but my charge against the Government is that they have not yet been able to make up their mind as to what kind of steps they should take in the matter of meeting this situation arising out of the alarming spread of sickness.

Sir, some time ago Tewari Committee was set up. The said committee made certain recommendations. They suggested that there should be a legislation passed by Parliament creating an apex body to function as a monitoring body and also take certain measures to prevent the incidents of sickness. They also recommended to devise ways and means so that the sickness may not get further deteriorated. So may I know from the hon. Minister of Industry whether the Government is contemplating to have a legislation of that nature. If so, by what time that kind of legislation or apex body as suggested by the Tewari committee is going to be set-up in terms of the proposed legislation.

17.00 Hrs.

Now, the question also comes as to the efficiency or efficacy or otherwise of the Industrial Development and Regulation Act. On more than one occasion in this House I have raised this, and the Govt. of West Bengal has also raised the question that unless the Industrial Development and Regulation Act is suitably amended to involve the State Governments in the

matter of monitoring, in the matter of running, in the matter of investigating the incidence of sickness, large number of units would become sick. Under the present Industrial Development and Regulation Act, the State Governments have got no role to play. They can't even report to the Govt. of India as a Government regarding certain mismanagement being indulged in a unit within a State, within its State's jurisdiction. They can't even report officially to the Govt. of India as to what impact it would have on the labour-situation, on the economy of the State. I am sorry to state that the states are kept completely outside the purview of the Industrial Development and Regulation Act. I would urge upon the Minister to see whether the time has not come now to examine about the efficacy of the Industrial Development and Regulation Act, to make suitable amendments that are needed, in order to involve State Governments at very stage so that there can be proper check and balance at every stage. Since it also concerns the Ministry of Labour, I would like to reproduce some portions of the 25th Indian Labour Conference proceedings where it has been stated as follows :—

> "Legislative provisions and Governmental machinery for take-over of sick units should ensure continuity of employment and production. Consequent upon the take over, there should not be any reduction in employment or emoluments, nor should there be any adverse effects on service conditions and benefits."

This is the principle laid down in the 25th Indian Labour Conference. My good friend, the hon. Labour Minister is not here. But to my greatest surprise I find that these very basic principles are being violated. For instance I can say about Inchek from my State about which he knows. There is the case of National Rubber ; now the question is whether the Government should nationalise it or not. Now it is being said that unless the workers or the unions agree to reduction of the component of labour, unless they give an undertaking that they accept some kind of wage freeze for 3 or 5 years, Government will not be in a position to nationalise the unit. May I ask you : Is it not in violation of the basic principles laid down in this 25th Labour Conference ? It unmistakably say—'There should be no reduction in labour employment ; there should be no reduction regarding conditions of service ; there should be continuity of production and employment.' Therefore my specific charge is, Government is reversing its own policy which it accepted during the 25th Labour Conference. The Government has stated as follows :

> "The Central Govt. should streamline procedures for take over and provide sufficient funds to run the units taken over."

Here the Inchek comes in National Rubber comes in. The workers made sacrifices to make the units viable. But now that is very much here. The Government will nationalise it. But a taken-over unit is not being nationalised on the ground that the workers do not agree to reduce the labour complement and they do not also agree to the proposal of wage freeze. My point is that the Government have gone back upon their commitments in the matter of nationalisation of the taken-over units. On the contrary, the Government is trying to denotify certain units which have already been taken over. So, if the Government does not have a firm position so that the workers can be assured of employment, necessary funds are made available and necessary corrective measures are taken to improve the managerial efficiency, sickness will continue and go on increasing. Therefore, I would, in conclusion, urge upon the Government to announce as to what positive and concrete steps Government proposes to take in order to meet the situation arising out of growing incidence of sickness in the industries of our country. I hope the hon. Minister would also inform the House whether any legislation as suggested by the Tiwary Committee is in the offing and if not, the reason for the same may be stated. If they do not want to accept the recommendations of that Committee, what other proposals they have to meet the situation which has already become alarming, before the situation goes out of the control of the Government ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेंडमेंट दिया है—

that is, after "employees" insert—

> "the root cause being the creation of workers as also the emergence of musclemen as leaders".

आज क्या हो रहा है, सारे मजदूर एक आवाज लगाते हैं कि मजदूर एकता जिन्दाबाद। ये मजदूर एकता जिन्दाबाद अगर एक हो जाते तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की एक बड़ी बीमारी खत्म हो जाती। चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इन मजदूरों की स्थिति के बारे में सोचा है। आज बंगाल की क्या स्थिति है ? पश्चिम बंगाल हिन्दुस्तान का एक भाग है, वहां कितने कत्ल और खून होते हैं, इस पर कभी किसी का ध्यान गया है। आपने 30 नवम्बर के "इण्डिया टूडे" में पढ़ा होगा।

Please see page 122 of the magazine under the heading "Murder in the Mill". It says like this.

> "The murder was the culmination of a two-hour long violent demonstration within the mill compound, during which no senior union leader tried to restrain them. Nor did the police think it necessary to intervene even though they had been informed.... He immediately called leaders of the six trade unions which operate in the mill (including the Marxist-dominated CITU and INTUC) and told them that payment would be made in the evening by when he expected the full amount to reach the mill...."

लेकिन यह रुपया नहीं पहुंचा—3 बजकर 30 मिनट पर। आप हालात को देखें—इन मजदूरों को उकसावा देने वाला कौन है और इसी लिये मैंने कहा था, मैं उस बात को सपोर्ट करना चाहता था।

This is what was stated in the Pioneer dated 30.10.1983.

> "Justice D. A. Das of the Supreme Court of India, today said that trade union rivalries and their association with political parties were hampering the progress of industry in the country. He said this while delivering his keynote address at the two-day seminar on Labour in a Democratic Society—The American Experience. The seminar was organised jointly by the National Institute of Personnel Management, UP Branch and United States Information Service, Delhi, at Hotel Clarks Avadh."

यह हालत है और इसका जो परिणाम निकला है, वह आपके सामने है। आज आप कुछ भी कहिए, लेकिन यूनियन-राइवलरी के लिये कौन एकाउन्टेबिल है ? पोलिटीकल पार्टीज इसके लिए जिम्मेदार हैं।

अभी दो दिन पहले ही हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा—हमारी जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उनसे हमें कम से कम 10 परसेन्ट लाभ मिलना चाहिये। हमारी इन पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में हमारा 20 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट है, उसका रिटर्न हमें कम से कम 10 परसेन्ट के हिसाब से मिलना चाहिये, लेकिन दुख की बात यह है कि—

Public sector undertakings have suffered a loss of 88 crores in the first quarter April-June, 1983-84. This is in contrast to the net profit of Rs. 130 crores registered during the corresponding period of 1982-83.

1982-83 में हमें 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, इस साल हम को कुछ लाभ हुआ है, जिससे हमारा कुल घाटा 88 करोड़ रुपए का हो गया। इसका कारण क्या है ? यह सवाल आप का और हमारा नहीं है, सारे देश का सवाल है। आपने प्रस्ताव में क्या लिखा है ? This Resolution is :

> "This House expresses its deep concern over the increasing incidence of industrial sickness and the consequent developing crisis in industry...."

पहली बात तो यह है कि सिकनेस का कारण क्या है ? हमारे उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे हमें इसके बारे में बतलाएं।

एक बात तो मुझे यह कहनी है कि आपकी जो फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज हैं उनके साथ सरकार के दूसरे डिपार्टमेन्ट्स का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर के हाथ में फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज हैं, इण्डस्ट्री का काम इण्डस्ट्री मिनिस्टर देखते हैं, लेबर मिनिस्ट्री को काम लेबर मिनिस्टर करते हैं इनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। धनपति आप की इंस्टीचूशन के पास जाता है--कर्जा लेने के लिये, उसका बड़ा स्वागत करते हैं, फाइव स्टार होटल की कल्चर शुरू हो गई है, चाहे जितना कर्जा ले लो। अब इंडस्ट्री वालों को यह मालूम नहीं है, उनके यहां कोई रिकार्ड नहीं है कि फलां इंडस्ट्री ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़ा चौकन्ना होता तो वह देखता कि वह इंडस्ट्री ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, थोड़ा उस पर चेक होता या रोक लगती। लेकिन होता क्या है- जब उस इण्डस्ट्री का दिवाला निकल जाता है तब कहते हैं कि इण्डस्ट्री सिक हो गई है। आज दत्ता सामंत ने हिन्दुस्तान को जो लास पहुंचाया है, करोड़ों रुपया का नुकसान कर दिया, क्या देश में कोई यह कहने वाला है कि दत्ता सामंत ने यह कर दिया। दत्ता सामन्त ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम को करोड़ों रुपया देकर सिक इण्डस्ट्री की मिलों को लेना पड़ा। इससे मजदूरों का भी नुकसान हुआ है। तो आज हम जिस बात की चर्चा करते हैं और बार-बार कहते हैं कि इस तरह से हम काम करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बात को कौन कहने वाला है कि इतना घाटा क्यों हुआ है।

कभी आपके सामने आंकड़े बताये गये और यह बताया गया था कि ये जो फिगर्स दिए हैं, वे करेक्ट फिगर्स थे। मैं उन फिगर्स को मानता हूं। 1981-82 के अन्दर 23,700 मिलें ऐसी थीं, जोकि सिक हैं और जिन का मनी ब्लोक कर दिया गया है। उनके अन्दर जो पैसा लगा हुआ है, वह ब्लोक हो गया है। इस संबंध में मैं आपको यह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "Mr. I Tiwari, Chairman of the Industrial Reconstruction Corporation of India, at the Corporation's latest annual meeting, said the number of sick units, large, medium and small, went up to 23,700 in 1981-82 blocking bank funds of the order of Rs. 1,900 crores. During the previous year, the number was 21,684, which blocked a total bank credit of about Rs. 1,745 crores." Now, within one year.

इतना रुपया रुक गया है, ब्लोक हो गया है। इसके लिये कौन जिम्मेवार है। आपका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स और लेबर डिपार्टमेंट है, इनमें कुछ भी काआर्डिनेशन नहीं है। न लेबर डिपार्टमेंट का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कोआर्डिनेशन है और न फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से कोआर्डीनेशन है। इन तीनों का एक दूसरे से कोई कोआर्डीनेशन न होने के कारण इन्डस्ट्री को लोस हो रहा है। आप बराबर पैसा देते रहते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इन्होंने आगे लिखा है :

> "Mr. Tiwari's explanation for this growing phenomenon of sickness is that firstly, in industries like jute and cotton textiles (which comprise the largest category of industrial units falling sick) many transferred funds elsewhere without any thought for their future modernisation...."

पैसा किसके लिये मिलता है ? डाइवर्शन करने के लिए और हम जो कर्जा देते हैं, उसका कितना उपयोग होता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके आगे वे लिखते हैं :

> "Mr. Tiwari has also not sufficiently stressed managerial incompetence or dishonesty, as major factors responsible for industrial sickness."

इतना रुपया इसमें लगा हुआ है। अब ये जो धंधा करने वाले हैं और यह जो मेनेजीरियल लोग हैं, इनकी कोई एकाउन्टेबिलिटी है। क्या इन से कभी पूछा गया है कि इतनी दौलत लेकर

आप मालदार हो गये हो और इतना पैसा हमारी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से मिलता है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों करते हो। उनको कोई इसके लिए कहने वाला नहीं है। हर इंडस्ट्री के अन्दर बहुत से यूनिट्स बीमार हैं और सबसे ज्यादा बीमार यूनिट्स बंगाल में हैं। वहां पर इतना हमारा पैसा रुका हुआ है। वेस्ट बंगाल में 98 ऐसे यूनिट हैं और 30 जून 1982 की जो पोजीशन है, उसके अनुसार 12,366.50 लाख रुपया इनमें सरकार का लगा हुआ है और बंगाल में सबसे ज्यादा यूनिट्स बीमार हैं और वे ही सबसे ज्यादा आवाज करते हैं कि हमारे यहां सिक मिलों की बीमारी है। यह जो बीमारी है, यह तो आपने ही पैदा की है और ये ही लोग इतना ज्यादा हल्ला करते हैं। दूसरे देशों में किस प्रकार से मिलें काम करती हैं और जापान में क्या ट्रेड है, उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जिसको सुन कर आप आश्चर्य करेंगे :

It says here.

> "...the Japanese people seem to have preserved their traditional work ethic. They work hard and not necessarily for more money. Hard work is seen as a means to improve oneself and as a means to improve oneself and as a means of contributing to the achievement of a company's goals. In Japan, workers tend to reach their work places earlier than the appointed hour and all of them concentrate on their work. Visitors to a Japanese factory cannot help notice that shop-floor workers pay little attention to the visitor even if he is accompanied by top executives. It is quite common for workers to put their own objectives or plans for improvement on the notice board so that non-achievement attracts group displeasure."

उनके अन्दर काम करने की भावना है। एक हमारे देश के अन्दर भावना है कि स्ट्राइक करो, नारा दो। मैं यह नहीं कहता कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हड़ताल करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है और अपने राइट के लिए लेबर को लड़ना है। जैसा मैंने कहा कि लेबर में राइबलरीज हैं। उनके तथाकथित लीडर्स हो जाते हैं जिनको लेबर लाज का पता नहीं है। वे जानते नहीं हैं कि लेबर लाज क्या हैं और बोलते इतने जोरों से हैं। अगर लेबर लाज की स्टडी की होती तो इतने सारे मुकद्दमें कोर्टों में नहीं पड़े हुए होते।

आप अगर देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि कितने मुकद्दमे लड़े जाते हैं। हजारों-हजारों की तादाद में मुकद्दमे आज ट्रिब्युनल्स में पड़े हुए हैं और वर्षों से पेंडिंग हैं। यहां से लेबर मिनिस्टर चले गये, उन्हें कोई काम होगा।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : श्रमिकों के इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और लेबर मिनिस्टर यहां नहीं है। इससे पता चलता है कि वे श्रमिकों के कितने हितैषी हैं। उन्हें श्रमिकों का हितैषी होना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : I don't think he said anything against the working classes.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : The Labour Minister should be in the House.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है। हम उसकी नीयत और नीति को समझते हैं और इस सदन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लेबर ट्रिब्युनल्स में जो केसिज पेंडिंग हैं उनकी संख्या 25 हजार, 27 हजार और 29 हजार है। इस पर भी आप लेबर को कसूरवार ठहराते हैं। आप लेबर का प्रोविडेंट फंड नहीं देते हैं। लेबर का सारा प्रोविडेंट फंड लोग खा जाते हैं। आपकी पब्लिक सेक्टर की बहुत-सी यूनिट्स ने लेबर का प्रोविडेंट फंड नहीं दिया है। इसको न देने के कारण लोगों में अशांति है। अगर आप देखें—

Here is a heading which says :

"437 Public units fail to implement Provident Fund Act."

इतना अमाऊंट है। क्या लेबर को प्रोविडेंट फंड देने का हमारा काम नहीं है? जितने केपटिलिस्ट्स हैं, पूंजीपति हैं आज हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं और हम पर पूंजीवादी डोमिनेट कर रहा है और हर तरकीब से कर रहा है।

The news report here says;

"A record number of 437 exempted public sector undertakings out of the total of 1175 have not complied either fully or partially with the statutory provisions of the Provident Fund Act, family pension and deposit-linked insurance schemes."

The report also says :

"It noted that a sum of Rs. 4.4 crores had not been invested by boards of exempted establishments....."

अब बताइए कि रुपया भी जमा नहीं है। लेबर का एक प्वाइंट बड़ा जबरदस्त है। लेबर को कोई देखने वाला नहीं है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में क्या है। आप उनका प्राविडेंट फंड ही जमा नहीं करते हैं। स्ट्राइक, लाक आउट, क्लोजर हर साल बढ़ रहा है।

You will kindly understand this. What about public undertaking Strikes, lockouts and closures—every year, it is increasing.

There is an answer given by Shri Dharmg Vir. It is dated 1st August, 1983. It says as follows :

"According to information received in the Labour Bureau, the number of strikes and lockouts during the years 1980, 1981 and 1982 is as follows :

YEAR	No. OF STRIKES AND LOCKOUTS
1980	2856
1981*	2589
1982*	2444

"Provisional"

Then he says in another answer on the same date as follows ;

"According to information received in the Labour Bureau, the total number of mandays lost was 21.93 million in 1980, 36.58 million in 1981 and 33.38 million (excluding the mandays lost due to the Bombay Textile Strike) in 1982." What was the year of 1982 ? It was the year or productivity.

उत्पादन वर्ष था। उस उत्पादन वर्ष में सबसे ज्यादा हमारा नुक्सान हुआ। आप इस फहरिस्त को देखिए—

Then he says further in the same answer as follows :

"While strikes have various, been due to demands over wages and allowances, personnel and bonus, lockouts have been largely due to indiscipline and violence, wages and allowances etc."

Who is accountable to all this violence ?

(*Interruptions*)

इन लोगों ने तबाही मचा दी थी जब बंगाल के अंदर दत्ता सामंत ने.....।

This is West Bengal and Kerala.

MR. DEPUTY SPEAKER : You must give a statement Stat-wise. Then you can blame a particular State Government.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I can place figures of each State.

MR. DEPUTY SPEAKER : If you have got the figures, then it is all right.

श्री मूल चन्द डागा : ये जो उधर के लोग बात करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं—

MR. DEPUTY SPEAKER : He is speaking on a general thing. He is not attacking anybody.

(*Interruptions*)

SHRI SATYAGOPAL MISRA (Tamluk) : He has been suffering from West Bengal fever.

(*Interruptions*)

SHRI MOOL DHAND DAGA : West Bengal is accountable for this.

SHRI SATYAGOPAL MISRA : Why is he talking about West Bengal ?

MR. DEPUTY SPEAKER : He has got his own reasons.

(Interruptions)

SHRI MOOL CHAND DAGA : You have got so much amount ; you have not utilized that amount. The best way for you is to cry about it near the factory. You can have it there and you can resort to murder or other things. We know what has happened in West Bengal.

आप लोगों को तो और नीची गरदन करनी चाहिए कश्मीर वालों को । ये क्यों बोल रहे हैं । 6 अक्तूबर को क्या हुआ । आपकी गरदन तो और नीची होनी चाहिए । 6 अक्तूबर को क्या हुआ : जब वेस्टइंडीज से मैच हो रहा था·····। (व्यवधान)

SHRI RAM LAL RAHI : I am on a point of order. *(Interruptions)*

PROF. SAIFUDDIN SOZ : What about Delhi ? Every day there is a murder. You are going to West Bengal ? You see the plunder and loot ; this is the Capital of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is going to conclude. Now, it is 5.30

MR. Daga may continue next time. All of you come prepared. We go to the next subject—Half-an-hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Grant of Loans to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Persons in Various States

MR. DEPUTY SPEAKER : We shall now take up discussion—Half-an-hour discussion regarding granting of loans to Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons.

SHRI RAM LAL RAHI (Misrikh) : Just two minutes, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : No.

SHRI RAM LAL RAHI : .....*

MR. DEPUTY SPEAKER : Please do not record anything.

Are you raising a point of order or what ? No I do not allow.

SHRI RAM LAL RAHI : .....*

MR. DEPUTY SPEAKER : No, not allowed. What do you want to speak ? Please reserve i for Monday. Please do not record anything. Shri Ram Vilas Paswan. It have taken up Half-an-hour discussion. Unless hon. Members obey the Chair, we cannot conduct the House. I have gone to the next subject. You have not given any notie. I will give you one hour on Monday. Mr. Ram Vilas Paswan.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : It is your commitment. You must give one hour.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes. Now, Mr. Ram Vilas Paswan ; Half-an-hour discussion on granting of loans to Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons in various States.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घण्टे की चर्चा हमारे प्रश्न संख्या-852 दिनांक 18 नवम्बर के अतारांकित प्रश्न से उठती है । आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति, जन-जाति या कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो सरकार द्वारा राशि दी जाती है, कितना उनके विकास पर खर्च किया जाता है, इसके बारे में मैंने लाइब्रेरी से सूचना मंगायी है जो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में है । इसमें अध्याय-26 है जिसमें लिखा है "संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों में से एक तत्त्व में बताया गया है" कि राज्य जनता में दुर्बलता विभागों में विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की

*Not recorded